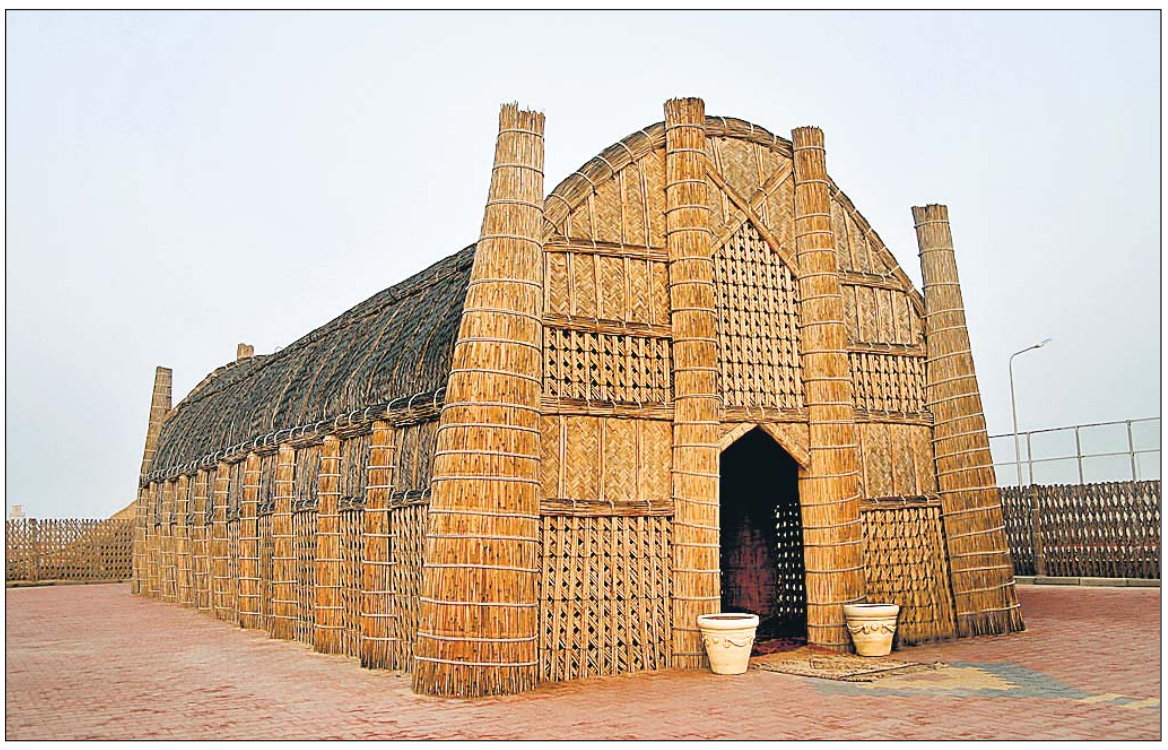

इराक के बारे में आपने खबरों में जितनी भी तस्वीरे देखी होंगी वो या तो युद्ध और हिंसा की होंगी या फिर रेगिस्तान की, यही वजह है कि पूरी दुनिया इस 5000 साल पुरानी संस्कृति से प्रायः अनभिज्ञ सी है जिसमें दक्षिणी इरान के मार्श अरब्स के "मडहिफ" भवन भी शामिल हैं। मडान लोग, चूंकि दलदल के करीब रहते हैं, इसलिए इन्हें मार्श अरब भी कहते हैं, इनकी आबादी लगभग 5 लाख से भी कम है। ये लोग अपने खास शैली में स्थापत्य वाले मडहिफ हाउस के लिए जाने जाते हैं। मडहिफ हाउस थोड़े से वक्राकार होते हैं तथा सरकंडे और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाए जाते हैं। गांव का शेख इनका रखरखाव करता है तथा इसके लिए सभी से कर वसूला जाता है। मडहिफ भवन मडान समाज के मुख्य केन्द्र हैं। इनमें मेहमानों को ठहराया जाता है तथा यहां धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। मार्श अरब कल्चर और मडहिफ भवन निर्माण कला को सद्दाम हुसैन के काल में सर्वाधिक नुकसान हुआ। चूंकि मार्श अरब लोगों ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ हुई बगावत को समर्थन दिया था इसलिए सद्दाम बेहद नाराज हो गया, उसने सत्तर के दशक की एक सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी जिससे क्षेत्र के दलदली भाग में होने वाला जल प्रवाह रुक गया और ये सूख गए, जो बचे खुचे जल क्षेत्र थे उनमें जहर डलवा दिया इनके घर जला दिए। इसके बाद इन लोगों ने पारम्परिक जीवन शैली छोड़ दी और वे गांवों व शरणार्थी शिविरों में रहने चले गए। पांच लाख लोगों में से सिर्फ 1600 लोग ही बचे हैं जो अब भी वहां पारम्परिक शैली के घरों में रहते हैं और जैसे तैसे अपनी संस्कृति व भवन निर्माण कला को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा

इंडिया गठबंधन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा की

नयी दिल्ली, 19 दिसम्बर। विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन ने संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के सदस्यों के निलम्बन के खिलाफ शुक्रवार (22 दिसंबर) को देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

गठबंधन के नेताओं की मंगलवार को यहां हुई बैठक में घटक दलों ने अगले आम चुनाव में जीत के लिए मिलकर काम करने और प्रदेश स्तर पर सीटों के तालमेल को मजबूत के उपाय करने का फैसला किया है।

बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, इंडी गठबंधन विपक्ष के सदस्यों के संसद से निलम्बन के खिलाफ 22 दिसम्बर को देशभर में विरोध प्रदेश करेगा। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा राज्यसभा और लोकसभा के कुल 141 विपक्षी सदस्यों को निलम्बित किया गया है और जैसा कि खड़गे जी ने कहा है कि, हम 22 दिसंबर को हर राज्य में इसके विरोध में मिलकर प्रदर्शन करेंगे।

- **कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि संसद से कुल 141 सांसद निलम्बित हुए हैं, इसके खिलाफ हरेक राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जाएंगे।**

खड़गे ने बैठक की जानकारी देते हुए यह भी कहा कि, हमारी मुख्य चिंता चुनाव जीतने और गठबंधन के सदस्यों की संख्या बढ़ ने की है। बैठक में तय किया गया है कि, गठबंधन के सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीटों के बंटवारे को लेकर स्थानीय स्तर पर बातचीत होगी और कहीं विवाद हुआ तो पार्टी के केंद्रीय नेता उसे सुलझाएंगे।

उन्होंने कहा कि, बैठक में सभी 28 दलों के नेता शामिल हुए और सभी ने बैठक को प्रभावशाली बनाया है और इसके लिए सभी दलों के नेता बधाई के पात्र हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक के बाद गठबंधन और मजबूत होगा।

गठबंधन के नेता के सवाल पर उन्होंने कहा कि, पहले मिलकर सीटें जीतनी हैं और उसके बाद मिलकर अपना नेता तय करेंगे। उन्होंने कहा कि दो-तीन राज्यों में जीत हासिल कर भाजपा का घमंड बढ़ गया है लेकिन इंडी गठबंधन पहले जीत हासिल करेंगे और उसके बाद सांसद किस तरह से अपने नेता का चुनाव करेंगे इस बारे में विचार किया जाएगा। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर सियासी घमासान के बीच इंडी गठबंधन की चौथी बैठक यहां अशोक होटल में बैठक हुई।

बैठक में कांग्रेस की ओर से खड़गे और जयराम रमेश के अलावा कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। बैठक में जनता दल के नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तृणमूल कांग्रेस नेता तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव और बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा राजद नेता तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले, आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, कम्युनिस्ट पार्टी के ए राजा तथा अन्य कई दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया।

विधानसभा का पहला सत्र आज से

- **पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, मुख्यमंत्री भजन लाल भी शपथ लेंगे।**
- **वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ को राज्यपाल ने प्रोटैम स्पीकर नियुक्त किया है, वे नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे।**
- **सत्र के दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। भाजपा ने स्पीकर पद के लिए वासुदेव देवनानी को उतारा है, चर्चा है कि, कांग्रेस भी उन्हें समर्थन दे सकती है।**

जयपुर, 19 दिसम्बर (का.सं.)। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार को बुलाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। सत्र के पहले दिन नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं, दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा, भाजपा की आरे से स्पीकर के दावेदार वासुदेव देवनानी की जीत तय मानी जा रही है।

वही सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस देवनानी को समर्थन दे सकती है, यदि विपक्ष देवनानी को समर्थन देता है तो उनका चुनाव निर्विरोध भी हो सकता है। राजस्थान में यह संभवत पहला मौका है, जब मंत्रिमण्डल के गठन से पहले विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। इससे पहले नई विधानसभा का पहला सत्र जनवरी में होता आया है, इसलिए सत्र से पहले मंत्रिमंडल का गठन हो जाया करता था।

नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने सबरे वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ को सोमवार को प्रोटैम स्पीकर नियुक्त किया था। कालीचरण सराफ को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को प्रोटैम स्पीकर पद की शपथ दिलाई थी। प्रोटैम स्पीकर के सहयोग के लिए राज्यपाल ने तीन सदस्यीय पैनल भी बनाया है। इसमें वरिष्ठ विधायक दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को शामिल किया गया है।

वही 16वीं विधानसभा में करीब 72 विधायक ऐसे हैं, जो पहली बार चुने गए हैं, इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हैं। वहीं, संभवत भजनलाल शर्मा पहले ऐसे विधायक हैं, जो विधायक से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर विधानसभा पहुंचेंगे। पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों में भाजपा के 46, कांग्रेस के 19 और अन्य 7 विधायक शामिल हैं। कालीचरण सराफ 16वीं विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। वे इस बार मालवीय नगर विधानसभा से चुनाव जीतकर 8वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। सराफ 1985 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। वे 4 बार जौहरी बाज़ार विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद जौहरी बाजार विधानसभा सीट समाप्त हो गई। इसके बाद से कालीचरण सराफ जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं।

जी.एस.टी. दूसरा संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित

संशोधन विधेयक जी.एस.टी. अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की आयु व योग्यता से संबंधित है

नयी दिल्ली, 19 दिसम्बर। लोकसभा ने जी.एस.टी. अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु एवं योग्यता में संशोधन के प्रावधान वाले केंद्रीय माल एवं सेवाकर (दूसरा संशोधन) विधेयक 2023 को मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

यह विधेयक वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में 13 दिसम्बर को पेश किया था और इसे चर्चा तथा पारित कराने के लिए आज पेश किया गया। इस विधेयक में जी.एस.टी. अधिनियम 2017 में संशोधन करके इसके प्रावधानों को ट्रीब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप करना है।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि, जीएसटी न्यायाधिकरण के गठन से देश में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में मामलों का बोझ कम होगा और जी.एस.टी. से जुड़े मुद्दों पर न्याय के लिए लोगों को लम्बे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और राज्यों में एक या दो पीठ होगी ताकि स्थानीय स्तर करदाताओं को सुविधा मिल सके।

उन्होंने कहा कि, विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र 50 साल रखी गई है जबकि अधिकतम उम्र 67 साल और अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र 70 करने का प्रावधान है। फिलहाल यह आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 67 और सदस्यों के लिए 65 वर्ष है।

सीतारमण ने कहा, सरकार का उद्देश्य है कि हमारी सूक्ष्म एवं मझौली इकाइयों-एम.एस.एम.ई. इकाइयों को कारोबार करने में आसानी हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जी.एस.टी. कानून में संशोधन से लघु क्षेत्र की इकाइयों को सावर्जनिक उपक्रमों से भुगतान में देरी नहीं होगी। सरकार एस.एस.एम.ई. इकाइयों के प्रति संवेदनशील होकर काम कर रही है।

इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के निशिकांश दुबे ने कहा कि, पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 2006-07 में कहा था कि, जी.एस.टी. लाएंगे लेकिन 2014 तक वह सरकार जी.एस.टी. को लेकर सिर्फ बातें ही करती रही क्योंकि वह टैक्स छोड़ने को तैयार नहीं थी। बीजू जनता दल की शर्मिष्ठा सेठी ने कहा कि, समिति की संस्तुति को क्रियान्वित करने की जरूरत है ताकि जीएसटी के दायरे में आने वाले सारे काम आसानी से हो सके। शिवसेना के धैर्यशील माणे ने कहा कि, न्यायाधिकरण जी.एस.टी. करदाताओं के सामने आने वाली दिक्कतों को मिलने वाली चुनौतियों के निदान के लिए आवश्यक है। जी.एस.टी. से जुड़े विवादों का इस विधेयक के आने से सुलझाया जा सकेगा। चर्चा में भाजपा के शंकर लालवानी तथा वाई.एस.आर. के श्रीकृष्ण डी लावू ने भी हिस्सा लिया।

- **यह विधेयक वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में 13 दिसम्बर को पेश किया था और इसे चर्चा तथा पारित कराने क लिए आज पेश किया गया। इस विधेयक में जी.एस.टी. अधिनियम 2017 में संशोधन करके इसके प्रावधानां को ट्रीब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुरुप करना है।**
- **सीतारमण ने कहा कि विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र 50 साल रखी गई है जबकि अधिकतम उम्र 67 साल और अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र 70 करने का प्रावधान हैं। फिलहाल यह आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 67 और सदस्यों क लिए 65 वर्ष है।**

'जमानत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पीड़ित को सुनवाई का मौका देने के लिए कहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें जमानत याचिकाओं में पक्षकार बनाया जाए। अदालत ने कहा कि पीड़ित पक्ष को कोई भी अधिकार देते समय यह भी जरूरी है कि आरोपी के अधिकारों की भी रक्षा की जाए।

प्रकरण से जुड़े अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट की एक एकलपीठ ने 8 अगस्त 2023 के दिए अपने आदेश में कहा था कि सभी जमानत याचिकाओं में पीड़ित को भी पक्षकार बनाया जाए, ताकि वह भी अपना पक्ष रख सके। इसके साथ ही एकलपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा था। जिस पर हाईकोर्ट प्रशासन ने 15 सितंबर को इस संबंध में निर्देश जारी कर जमानत याचिकाओं में पीड़ित या शिकायतकर्ता को जरूरी तौर पर पक्षकार बनाए जाने का निर्देश दिया। आज हाईकोर्ट की खण्डपीठ को इस मुद्दे पर स्पष्टता से फैसला देना था कि जो शर्तें विधानसभा ने कानून में नहीं डाली है, क्या वही शर्तें अदालत कानून को पढ़ते समय जोड़ सकती है? यानि वर्तमान मामले में जो शर्तें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) में जमानत याचिका पेश करने के लिए नहीं लगाई गई है, क्या कोई अदालत उनमें अलग से शर्तें जोड़ सकती है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में एक अन्य एकलपीठ ने पूजा गुर्जर व अन्य की जमानत याचिकाओं में अपना मत दिया कि ऐसे मामलों में परिवादी या पीड़ित पक्ष को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही एकलपीठ ने प्रकरण में दो अलग-अलग मत होने के चलते इस बिंदु को तय करने के लिए खंडपीठ में भेज दिया था। आज खण्डपीठ ने इस विवाद को खत्म करते हुए कहा है कि जमानत याचिकाओं में परिवादी या पीड़ित को पक्षकार बनाना जरुरी नहीं।

खड़गे को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की ओर प्रधान पद का चेहरा घोषित करने के बारे में कोई भी निर्णय आम चुनावों में किया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि बनर्जी ने इस प्रस्ताव को विपक्षी इंडिया गठबंधन की चल रही बैठक को ध्यान में रखते हुए इसलिए तैयार किया था ताकि इंडिया गठबंधन की लोकप्रिय छवि को प्रचारित किया जा सके कि यह गठबंधन कमजोर और दबे कुचले दलितों के लिए कार्य कर रहा है। विपक्ष में खड़गे दलित के रूप में प्रमुख चेहरा हैं और इस योजना को व्यापक स्तर पर मंजूरी मिल जाएगी।

बनर्जी ने कहा कि "जब बहुत सारे राजनीतिक दल एक साथ नजर आ जाए तो यह लोकतंत्र है भिन्न-भिन्न राज्यों, जिनका अलग-अलग दृष्टिकोण एवं पृथक-पृथक राय हो, परन्तु अन्ततोगत्वा इंडिया एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम सब मिलकर एक साथ संघर्ष कर रहे हैं।"

ममता ने कहा कि, "भाजपा का कोई गठबंधन नहीं है। एन.डी.ए. अब खत्म हो चुका है। हम उनकी तरह नहीं है। यह अच्छा ही होगा कि आम चुनावों के परिणाम दखेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। इसका फैसला सभी पार्टियां मिल बैठकर करेगी।"

बनर्जी ने यह भी कहा कि "आप यह निर्णय कर सकते हैं कि किस प्रकार एक पार्टी जनता व मातृभूमि लिए अच्छा कार्य कर सकती है। आपको भारत की जनता को उनकी भलाई के लिए प्राथमिकता देनी होगी। अभी जो शासन चल रहा है वह निरंकुश तंत्र है जिसे कोई भी आमजन नहीं चाहता है।"

बनर्जी ने खड़गे का प्रस्ताव इसलिए किया था ताकि जनता में यह संदेश बिल्कुल सीधा जाए कि इंडिया गठबंधन के दल सत्ता प्राप्ति के भूखे नहीं है बल्कि यह स्पष्ट संदेश है कि वे ऐतिहासिक उद्देश्य के साथ एक दलित व्यक्ति को देश के सर्वोच्च शासक पद पर पदस्थापित करना चाहते हैं।

इस बात ने मीडिया में खलबली मचा दी। मीडिया ने पहले से ही खड़गे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव को उछालना शुरू कर दिया और वह इसे राहुल गांधी के लिए झटका बता रहा है। हालांकि राहुल लगातार यह बात दोहराते आ रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री की कुर्सी की दौड़ में सम्मिलित नहीं है। राहुल एक ही नहीं अनेक अवसरों पर कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई विचारधारा की है न कि सत्ता के लिए।

विपक्षी नेताओं से कहा गया है कि संयुक्त प्रचार अभियान चलाने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार करें, सीटों की सहभागिता की व्यवस्था और वे अपनी रणनीति को पुन: नया रूप दें अभी कुछ समय पूर्व सम्पन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को पराजय से काफी झटका लगा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के चुनावों में भाजपा ने जीत दर्ज की है।

इंडिया गठबंधन की यह चतुर्थ बैठक हुई है। इस गठबंधन की पहली बैठक पटना में 23 जून को, बेंगलुरू में द्वितीय बैठक 17-18 जुलाई एंव तृतीय बैठक मुम्बई में 31 अगस्त व 1 सितम्बर को हुई थी।

इंडिया गठबंधन की इस बैठक में वरिष्ठ नेतागण सहित सी.पी.पी. अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी उपस्थित थे। इनके अतिरिक्त ममता बनर्जी, तमिलनाडू मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली व पंजाब के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल एवं भगवंत मान तथा एन.सी.पी. के अध्यक्ष शरद पवार भी बैठक में उपस्थित थे।

श्रीनगर, पहलगाम का तापमान और गिरा

श्रीनगर, 19 दिसंबर। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान शून्य से कम 3.7 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में शून्य से कम 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी।

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सोमवार को पर्यटक स्थल के लिए तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम था जबकि मंगलवार को यहां का तापमान शून्य से कम 5.1 डिग्री सेल्सियस, पुलवामा में शून्य से कम 5.5 डिग्री सेल्सियस, शोपियां में शून्य से कम 6.8 डिग्री सेल्सियस और कुलगाम में शून्य से कम 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुलमर्ग में आज तापमान शून्य से कम 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है।

राज्यसभा में अव्यवस्था के कारण कार्यवाही स्थगित

नयी दिल्ली,19 दिसंबर। संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने मंगलवार को लगातार चौथे दिन राज्यसभा में अव्यवस्था पैदा की जिसके कारण सदन की कार्यवाही चार बार के स्थगन के बाद पांच बजे तक स्थगित करनी पड़ी। स्थगन के बाद चार बजे जैसे ही कार्यवाही दोबारा शुरू हुई किसी सदस्य ने राम राम कह कर सभापति का अभिवादन किया। सभापति ने कहा कि राम राम से एक किस्सा याद आ रहा है।

सभापति ने किस्सा सुनाते हुए कहा कि, एक बार एक बस में एक बुजुर्ग के पास सीट पर बैठा युवक सिगरेट पी रहा था। वह बार-बार सिगरेट का धुंआ ताऊ की ओर छोड़ रहा था। ताऊ इससे परेशान था । इसी बीच सिगरेट से निकली एक चिंगारी ताऊ की धोती पर गिर गयी लेकिन ताऊ ने इसे भी नजरंदाज किया तो युवक को महसूस हुआ कि, उसने सीमा पार कर दी है। उसने ताऊ से पूछा कि आप किस गांव के हो , तो ताऊ ने तपाक से जवाब दिया कि क्या अब उसे गांव भी फूंकना है।

उन्होंने कहा कि, विपक्ष ने सभी सीमा पार कर दी है। सभापति ने विपक्षी सदस्यों से कहा , आपने अब तक जो किया सो किया आगे क्या करना है। पूरा दिन इतना दुखी रहा है और क्या करोगें।

सभापति ने कहा कि, बाहर और भीतर जो कुछ भी हो रहा है यह बहुत चिंता का विषय है । इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले विपक्षी सदस्यों के हंगामें के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे, फिर अपराह्न दो बजे, भोजनावकाश के बाद तीन बजे तक और फिर अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

आडवाणी व...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आलोक कुमार ने कहा कि, राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और आदरणीय डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी को अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि निमंत्रण देते समय राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में भी बातें हुईं। इससे पहले चर्चा थी कि आडवाणी और जोशी प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। कारण बढ़ती उम्र व खराब स्वास्थ्य को बताया गया था।

विपक्ष मुक्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा।थरूर ने आगे यह भी कहा कि "आज मंगलवार है, मेरे साथी सांसदों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए, मैंने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और जो कोई भी वहां उपस्थित था उसे संसद के शेष रहे सत्र की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया गया, इसका मतलब साफ है कि वे उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयकों को बगैर कोई चर्चा-बहस के पारित करना चाहते हैं। मुझे लगता है यह संसदीय लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है।"

कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी, वो भी उन सांसदों में से एक हैं, जिन्हें मंगलवार को निलम्बित किया गया था, ने कहा, "संसद की वैधानिक प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया गया है।" उन्होंने कहा, यह सब कार्यवाही अत्यन्त क्रूर कानून को पारित करने के लिए की गई है, इस कानून की वजह से देश पुलिस राज स्थापित हो जाएगा।

संसद से अब तक 141 सांसदों को निलम्बित किया जा चुका है, जिसमें से 34 राज्यसभा के और 107 लोकसभा के सदस्य हैं।

तेलंगाना के बाद अब कांग्रेस का फोकस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सत्तारूढ़ वाय.एस.आर.सी.पी. चिन्तित है, क्योंकि तेलंगाना के परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस की थोड़ी-बहुत लोकप्रियता अभी बरकरार है और तेलंगाना में लोक लुभावन राजनीति कर लोकप्रिय बने पूर्व मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव को जिस तरीके से सत्ता से बाहर किया गया, पार्टी यहां भी रैवन्त रेड्डी का आक्रामक मॉडल अपनाकर अपना पुनरुत्थान कर सकती है।

आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय संदर्भ में भी महत्व है क्योंकि यहां से 25 सांसद निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचाते हैं। वर्तमान में सत्तारूढ़ वाय.एस.आर.सी.पी. के यहां से 23 लोकसभा सांसद हैं। लोकसभा चुनावों के साथ ही आंध्र प्रदश में विधानसभा चुनाव होंगे।

आंध्र प्रदेश में वाय.एस.सी.आर.पी. एवं जगन मोहन रेड्डी सरकार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं, लेकिन विडम्बना यह है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का पुनरुत्थान सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि इससे उन सत्ता विरोधी मतों का विभाजन हो जाएगा जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री एवं टी.डी.पी. सुप्रीमो एन. चन्द्रबाबू नायडू अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। संयोगवश, आंध्र प्रदेश की राजनीति सत्तारूढ़ वाय.एस.आर.सी.पी. और तेलुगु देसम पार्टी के रूप में दो घोड़ों की रेस बनकर रह गई है और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा व कांग्रेस यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रही हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी टी.डी.पी. ने फिल्म स्टार से राजनेता बने पवन कल्याण के साथ गठबंधन किया है और पवन कल्याण का भाजपा के साथ अच्छा तालमेल है।

भाजपा की आंध्र प्रदेश में फिलहाल कोई भी उपस्थिति नहीं है, लेकिन वह यहां लोकसभा चुनावों के संभावित परिणामों को लेकर चिन्तित है और यहां से जीतने वाले वाय.एस.आर.पी. या टी.डी.पी. यदि केन्द्र में भाजपा का समर्थन करेंगे तो उसे प्रसन्नता होगी।

जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से बाहर करने के लिए टी.डी.पी. भाजपा के साथ गठजोड़ की इच्छित रहती आयी है, लेकिन जगन मोहन का आंध्र प्रदेश और अपनी पार्टी पर आज भी कड़ा नियंत्रण है। उनकी पार्टी पिछले तीन वर्षों से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है।

तेलंगाना के चुनाव परिणामों के बाद जगन मोहन ने भी अपनी जीत पर फोकस करना शुरु कर दिया है और उम्मीद है कि वह वे गलतियां नहीं करेंगे जो के.सी.आर. और उनकी पार्टी ने तेलंगाना में की थीं। वह संसद में भी अपने राज्य को अपनी ग्रिप में रखना चाहते है और आंध्र प्रदेश की कुल 25 में से अधिकांश सीटें जीतकर वर्ष 2019 के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार जगन मोहन अपनी पार्टी के कुल 151 विधायकों का टिकट काट सकते है क्योंकि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसा के.सी.आर. ने नहीं किया था। उन्होंने टिकटों के वितरण में अपने प्रति निष्ठा को ही प्राथमिकता दी थी।

लेकिन आंध्र प्रदेश राजनीतिक लय एवं व्याकरण को गड़बड़ाकर कांग्रेस का प्रयास अपना पुनरुत्थान करना होगा, जो कि वाय.एस.आर.सी.पी. के बजाए टी.डी.पी. को अधिक चिन्तित कर सकता है, किन्तु कांग्रेस यदि अपने कुछ नेताओं की वाय.आर.एस.आर.पी. से वापसी करवाने में सफल हो जाती है तो आंध्र में उसकी उपस्थिति एवं पुनरुत्थान दोनों विपक्षी पार्टियों में से एक को नुकसान पहुंचा सकता है और यहां के मुखर होते राजनीति ड्रामा में सब को चौंका सकता है।

तेलंगाना के चुनाव परिणामों के बाद आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने कई मीटिंग्स कर नवजीवन के संकेत देने शुरु कर दिए हैं जिससे पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आंध्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवाजी को एक स्थानीय तेलुगु मीडिया में यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि "कर्नाटक और तेलंगाना के बाद हमारा लक्ष्य आंध्र प्रदेश है। चूंकि हम विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र पार्टी का मजबूत कर रहे है, इसलिए हमें यहां कापू और पिछड़ी जातियों को अधिक तवज्जो देने की जरुरत है।

बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी हैं लेकिन इनमें ज्यादा दम नहीं है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कुछ ऐसा ही कहते हुए आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की आकांक्षाओं को खारिज किया क्योंकि कांग्रेस को वर्ष 2014 के बाद से यहां सिर्फ 1.5 प्रतिशत वोट हासिल हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की दीर्घकालीन "ब्रैण्ड इमेज" और दक्षिण भारत में उसके पुनर्जीवन को देखते हुए वह आंध्र प्रदेश में वह किसी अन्य पार्टी की संभावना को खत्म करने में सक्षम है।

आखिरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करिश्माई नेता राजस्थान में कांग्रेस को उभारने में मद्दगार हो सकता है।

एक सीनियर नेता ने कहा कि "राजस्थान की राजनीति में जितना संभव हो सकता था, गहलोत उतना नुकसान कांग्रेस को पहले ही पहुंचा चुके हैं और उनकी यदि रिटायर होने की इच्छा नहीं है तो उनका राजस्थान की राजस्थान से दूर रहना ही बेहतर होगा।"

आखिर क्या...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्यकर्ता के हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने वादा किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर चाहे कुछ भी हो, वह तृणमूल के खिलाफ कड़ा संघर्ष करेगी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908